साप्ताहिक

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 17-3 अप्रैल, 2023, 2023, वर्ष-9, अंक-01

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

-सामान्य से कम होगी बारिश, खेती को लेकर बढ़ी चिंता: स्काइमेट

## सावधान! सूखा रहेगा मानसून

» गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश बहुत कम होने का दावा

» सीजन की दूसरी छमाही में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान

» भारत में अनाज की पैदावार कम हो सकती है, इससे महंगाई बढ़ेगी

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

मौसम का अनुमान लगाने वाले स्काइमेट ने आशंका जताई है कि आगामी जून से सितंबर में मांनसून सामान्य से नीचे यानी सूना ही रहेगा, जिसने देश में खेती को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्काईमेट ने जून से सितंबर तक चार महीने की लंबी अवधि के लिए 868.6 मिलीमीटर बारिश का अनुमान लगाया है, जो दीर्घ अवधि के औसत (एलपीए) का 94 फीसदी हो सकता है। ला नीना के चलते पिछले लगातार चार साल में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से अधिक रहा। अब ला नीना समाप्त हो गया है और अल नीनो के आसार बढ़ रहे हैं। मानसून के दौरान अल नीनो के प्रभावी रहने की आशंका है। स्काईमेट के मुताबिक अल नीनो की वापसी से मानसून के कमजोर पड़ने का अनुमान है। देश के उत्तरी और मध्य भागों में बारिश के कम होने के आसार हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जुलाई और अगस्त के मानसूनी महीनों के दौरान बारिश में भारी कमी होने की आशंका जताई है। स्काईमेट ने कहा कि उत्तर भारत के कृषि क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीजन की दूसरी छमाही में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है।

### मौसम होगा प्रभावित

अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में जलवायु पैटर्न हैं जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर सकते हैं। अल नीनो और ला नीना की घटनाएं औसतन हर दो से सात साल में होती हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार की नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार, वे नियमित समय पर नहीं होती हैं।

### मार्च बारिश से घटेगा उत्पादन

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अभी तक मांनसून के पूर्वानुमान को जारी नहीं किया है, लेकिन इस गर्मी में तापमान के सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। किसान आमतौर पर पहली जून से गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों की बोवनी शुरू करते हैं, जब मानसूनी बारिश आमतौर पर भारत पहुंचती है। दूसरी ओर मार्च में हुई बेमौसम बारिश से रबी फसल के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है।

### मानसून की संभावनाएं

**जून - एलपीए का 99 फीसदी**

बारिश के सामान्य होने की 70 फीसदी संभावना
बारिश के सामान्य से ऊपर होने की 10 फीसदी
बारिश के सामान्य से कम होने की 20 फीसदी

**जुलाई - एलपीए का 95 फीसदी**

बारिश के सामान्य होने की 50 फीसदी की संभावना
बारिश के सामान्य से ऊपर होने की 20 फीसदी संभावना
बारिश के सामान्य से कम होने की 30 फीसदी की संभावना

**अगस्त - एलपीए का 92 फीसदी**

बारिश के सामान्य होने की 20 फीसदी संभावना
बारिश के सामान्य से ऊपर होने की 20 फीसदी
बारिश के सामान्य से कम होने की 60 फीसदी

**सितंबर - एलपीए का 90 फीसदी**

बारिश के सामान्य होने की 20 फीसदी संभावना
बारिश के सामान्य से ऊपर होने की 10 फीसदी
बारिश के सामान्य से कम होने की 70 फीसदी

-मुरैना की गजक, ग्वालियर के कार्पेट, रीवा का आम बना 'खास'

## मप्र के छह उत्पादों को पहली बार एक साथ मिला GI टैग

» अब प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर 19 हुई

» डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, बालाघाट के वारासिवनी की रेशम साड़ी की बढ़ी मांग

**भोपाल।** मध्यप्रदेश के हस्त शिल्प उत्पादों ने नया इतिहास रचा है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एडं इंटरनल ट्रेड ने मध्यप्रदेश के छह उत्पादों को जीआई टैग दिया है। इनमें डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कार्पेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासिओनी की साड़ी और रीवा का सुंदरजा आम शामिल हैं। यह पहला अवसर है कि जब एक साथ मध्यप्रदेश के आधा दर्जन उत्पादों को जीआई टैग मिला है। साथ ही प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। मप्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक और संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम की सीईओ अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि जीआई टैग एक प्रकार का लेवल है, जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। यह केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय तय करता है।

### कलाकारी के अच्छे दिन

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेडाघाट का सौंदर्य का आधार यहां की संगमरमरी वादिया है। इन्हीं संगमरमर के पत्थरों को तराशकर कलाकार, मूर्तियां, सीनरी, नाम पट्टिका और मार्बल ज्वैलरी आदि का निर्माण करते हैं। भेड़ाघाट के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग, जिलहरी, गणेश, दुर्गा आदि देवी- देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा।

### अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। मुरैना की गजक का स्वाद, देश ही नहीं दुनिया में सराहा जा रहा है। रीवा के सुंदरजा आम की मिठास अद्भुत है। प्रदेश का चंबल और विंध्य क्षेत्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। मुरैना की गजक और रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टेग मिलने से इन क्षेत्रों की राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनेगी। विंध्य और चंबलवासियों को बधाई।

### कालीन इंडस्ट्री तैयार की जाएगी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के कालीन कारोबार को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार और उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। जिसके लिए चंदेरी की तर्ज पर ग्वालियर में कालीन इंडस्ट्री तैयार की जाएगी। प्रॉडक्शन के लिए सभी जरूरतें पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री तोमर ने कार्पेट की फैक्ट्री की शुरुआत की, जिसे हम आगे ले जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सबसे बड़ी लूम की फैक्ट्री ग्वालियर में स्थापित हो।

उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की संयुक्त कार्य-योजना

## ग्वालियर में बनेगी प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब

भोपाल। जागत गांव हमार

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लेब की स्थापना ग्वालियर में होगी। लेब का कार्य अगले माह के पहले सप्ताह में शुरू किया जायेगा। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड और उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की संयुक्त कार्य-योजना में सम्मिलित हाईटेक फ्लोरीकल्चर नर्सरी और एयरोपोनिक्स लैब की स्थापना के बारे में मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

### भोपाल में जल्द ही शुरू होगा फ्लावर डोम निर्माण

श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी विभाग के प्रस्ताव पर भोपाल में फ्लावर डोम निर्माण को भी जल्द ही शुरू किया जायेगा। इसके लिये कार्य-योजना तैयार की गई है। फ्लावर डोम के लिये मण्डी बोर्ड और उद्यानिकी विभाग के एमआईडीएच कार्यक्रम से 836 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि, मण्डी बोर्ड एवं उद्यानिकी और खाद्य प्र-संस्करण विभाग के समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिये कहा गया। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने चेन फेंसिंग योजना को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। कृषि उत्पादन आयुक्त वीरा राणा ने कहा कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कार्यों के प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयों को भेजने के बाद समय-समय पर प्रगति की जानकारी भी प्राप्त करें।

### क्रियान्वयन के लिए दिया गया निर्देश

कार्यों की स्वीकृति अथवा अन्य किसी स्तर पर कटिनाई पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा कर उसे दूर करें। अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि विभागीय कार्यक्रमों को पूरी सजगता के साथ क्रियान्वित करें। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सहित अन्य कायक्रमों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक वर्णवाल, एमडी मण्डी बोर्ड जी.क़ी. रश्मि और एमडी एमपी एग्रो संजय गुप्ता उपस्थित थे।

## मध्यप्रदेश शरबती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक

### -देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला गेहूं माना गया है
### -चपाती में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी और ई प्रचुर मात्रा में

# शरबती गेहूं को जारी हुआ जीआई टैग सीहोर सर्वाधिक उत्पादक जिला

भोपाल। जागत गांव हमार

शरबती गेहूं मुख्य उत्पादक जिला सीहोर के साथ विदिशा जिले में उगाई जाने वाली एक क्षेत्रीय किस्म है। इसके दानों में सुनहरी चमक होती है। इस गेहूं की चपाती में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरबती गेहूं को आवेदन क्रमांक 699 के संदर्भ में जीआई टैग जारी किया गया है। देश में शरबती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला सीहोर है और मध्यप्रदेश शरबती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है। शरबती गेहूं का आटा देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला माना गया है। जिले में सर्वाधिक उत्पादक शरबती गेहूं के दाम भी किसानों को उच्चतम स्तर के प्राप्त होते हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ती है। वैसे तो भारत जैसे विशाल देश में अधिकतर राज्यों में गेहूं की खेती की जाती है। अच्छा उत्पादन भी होता है। लेकिन मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के शरबती गेहूं की पूरे भारत में अलग ही बात है, क्योंकि यह गेहूं देखने में सोने जैसा चमकीला है। इसके सभी दाने एक समान होते हैं। शरबती खाने में भी मीठा है। तभी तो देश भर में शरबती अपनी शान बिखेर रहा है। हर राज्य में इसके चर्चे हैं।

### बंपर पैदावार होने का अनुमान

शरबती गेहूं की इस बार सीहोर में बंपर पैदावार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश का 50-60 प्रतिशत शरबती गेहूं सीहोर में ही पैदा होता है। इसका आटा खाने में मीठा होता है, इसलिए इसको शरबती नाम दिया गया है। सीहोर के अलावा अन्य जिलों में भी शरबती गेहूं बोया जाता है। गेहूं की सभी किस्मों में यह सबसे महंगा बिकता है। अमूमन शरबती गेहूं के दाम 2,800 रुपए से लेकर 4,000 रुपए क्विंटल तक रहते हैं। जबकि अन्य गेहूं के इतने अधिक दामों पर नहीं बिकता है।

### इसलिए खास शरबती गेहूं

शरबती गेहूं का रंग सुनहरा होता है और इसके दाने एक समान होते हैं। यह हथेली पर भारी लगता है, लेकिन इसका स्वाद मीठा होता है। इसलिए इसका नाम शरबती है। गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज जैसे सरल शर्करा की मात्रा अधिक होती है। सीहोर में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार होती है। इसकी वजह सीहोर क्षेत्र में पाई जाने वाली काली और जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है, जो शरबती गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त होती है। शरबती गेहूं में सी-306 किस्म बेस्ट मानी जाती है। इसकी क्रॉस वैरायटी भी बाजार में उपलब्ध है।

### आधा दर्जन राज्यों में जा रहा शरबती

वैसे तो सीहोर के शरबती गेहूं की पूरे भारत में मांग है। लेकिन सबसे अधिक तमिलनाडु, गुजरात, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से कई कंपनियां सीजन के समय सीहोर में आकर खुद शरबती गेहूं की खरीदी करती हैं। कृषि विभाग की मानें तो औसत के मान से शरबती गेहूं की उपज एक हेक्टेयर में करीब तीस क्विंटल तक आती है। जिन किसानों के पास पानी की अच्छी उपलब्धता है, वे 40 से 50 क्विंटल प्रति हैक्टेयर तक भी शरबती का उत्पादन लेते हैं।

## 586 किसानों ने संतरा, मौसम्बी, आम, अमरूद, नींबू और सीताफल की खेती में जुटे

# तीन वर्षों में नर्मदा के 809 हेक्टेयर रकबे में फैली हरियाली की चादर

संजय शर्मा, खरगोन।

निमाड़ की उर्वरा भूमि और नर्मदा का जल हर मौसम की फसलों के लिए अनोखा वरदान है। नर्मदा नदी के जल को कल-कल और निर्मल रखने के लिए मप्र शासन ने वर्ष 2017 में नमामि देवी नर्मदे योजना प्रारम्भ की। इस योजना में नदी के दोनों किनारों पर 2-2 किमी. के दायरे में हरियाली की चादर बिछाने का निर्णय लिया गया था।

आज 2017-18 और 218-19 में बड़वाह, महेश्वर और कसरावद के 809.01 है. रकबे में 586 किसानों ने संतरा, आम, अमरूद, नींबू, सीताफल और मौसम्बी की खेती से हरियाली की चादर बिछाई है। इन किसानों को योजना के तहत 438.23 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। ये बागीचे आज किसानों को भरपूर फल प्रदान कर अच्छा मुनाफा भी देने योग्य हुए हैं। साथ ही मिट्टी के कटाव और नर्मदा जल को निर्मल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे योजना में लाभान्वित होने वाले बेटे और पौते ऐसे किसान हैं जो अपने दादा द्वारा 1970 के दशक में देखें सपने को इस योजना के माध्यम से पूरा कर रहे है।

आज से करीब 50 साल पहले 1970 में बहेगांव के नवलसिंह मांगीलाल सोलंकी ने निमा? के गर्म मौसम में मौसम्बी की खेती का आगा? किया था। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ यह बात पौते (राजेन्द्र सोलंकी) के मन में बस गई। जब पौते के हाथों में खेती की बागडोर आयी तो मौसम्बी का बगीचा लगाने का सपना जागा। इस बीच मप्र द्वारा नमामि देवी नर्मदे योजना के तहत हरियाली बिछाने का निर्णय लिया गया। तो सबसे पहले राजेन्द्र ने अपने पिता भगवान मांगीलाल सोलंकी के साथ मिलकर बगीचा बसाने की फिर शुरुआत की। पहली बार मौसम्बी के बगीचे में एक पौधे पर करीब 1-1 क्विंटल तक के फल आये। राजेन्द्र बताते है जैसे उनके दादा का कोई अधूरा सपना पूरा हो गया है।

### बच्चें ने खेती के लिए की कृषि में बीएससी

राजेन्द्र ने खेती को उन्नत तरीके से करने के लिए अपने बेटे दीपेंद्र को इंदौर से कृषि में बीएससी की शिक्षा दिलाई है। राजेन्द्र का कहना है कि आज के दौर में कृषि की शिक्षा अनिवार्य है। खेती को उन्नत तरीके से करने के लिए न सिर्फ रासायनिक बल्कि जैविक ज्ञान के अलावा नई विधियों व बाजार तथा मौसम की जानकारी होनी चाहिए।

### जैविकता से फलों में बिखरी शक्कर सी मिठास

राजेन्द्र के बागीचे की मौसम्बी की एक खासियत यह भी है कि 6 वर्षों से खेत में कोई भी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग नहीं किया। इस कारण फलों की ताजगी और शक्कर सी मिठास आयी है। 2017 में राजेंद्र के खेत में 3 है. रकबे में करीब 1700 पौधे और पिता भगवान सोलंकी के खेत में 1110 लगाए थे। पहली ही फसल से उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ है।

## मप्र में 70 हजार हेक्टेयर में फसल प्रभावित होने की रिपोर्ट दे चुके जिले

# ओलावृष्टि से आहत किसानों को अप्रैल के अंत तक मिलेगी राहत

भोपाल। जागत गांव हमार

पिछले दो दिनों में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहान में रखी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह खरीदी केंद्रों पर उपार्जित गेहूं खुले में रखा हुआ था, उसे भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन करने के लिए कहा है। वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों से कहा है कि वे जितनी भी उपज खरीदें, उसके सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करें। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण इस महीने के अंत तक किया जा सकता है। प्रदेश में ओलावृष्टि और वर्षा से रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। राजस्व विभाग के सर्वे में अब तक 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट जिले दे चुके हैं। पिछले दो दिन में हुई ओलावृष्टि और वर्षा से खेत व खलिहानों में रखे गेहूं को नुकसान पहुंचा है।

### पंचनामा भी बनाया गया

पूर्व कृषि संचालक जीएस कौशल का कहना है कि कटी फसल पर पानी पड़ने से दाने खेत में ही गिर जाते हैं। जो बाली पानी में दब जाती है, वह फूलकर खराब हो जाती है। ऐसे में किसान को नुकसान पहुंचना तय है। उधर, राजस्व और कृषि विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि फसल को पहुंची क्षति का आकलन किया जाए। पंचनामा बनाकर उसकी जानकारी ग्रामीणों को भी दी जाए।

- सभी उपार्जन केंद्रों के प्रभारियों से कहा गया है कि उपार्जन के साथ-साथ भंडारण की व्यवस्था करें ताकि उपज खराब न हो। जहां-जहां भी ओलावृष्टि या वर्षा से फसल प्रभावित हुई है, वहां सर्वे करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण भी जल्द अप्रैल-मई में ही किया जाएगा।

**गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री**

### केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर दी सहमति, मई तक भर दिए जाएंगे जिलों में खाद के गोदाम

# मध्य प्रदेश करेगा 11 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण

भोपाल। जागत गांव हमार

चुनावी साल में किसानों को खाद की कमी न आए, कहीं भी लाइनें न लगें, इसके लिए सरकार खरीफ सीजन प्रारंभ होने के पहले ही गोदामों में खाद पहुंचा देगी। इसके लिए 11 लाख टन का अग्रिम भंडारण किया जा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य के प्रस्ताव से सहमत होते हुए खाद भेजना भी शुरू कर दिया है। मई तक खाद का भंडारण हो जाएगा और किसान अपनी सुविधा के अनुसार पहले खाद भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ब्याज भी नहीं देना होगा। प्रदेश में कुछ वर्षों से खाद की कमी सामने आ रही है। पिछले साढ़े आठ लाख टन खाद के अग्रिम भंडारण का कार्यक्रम बनाया गया था लेकिन साढ़े पांच लाख टन ही मिल पाई। इसके कारण कमी आई और कई स्थानों पर किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए दो-दो दिन लाइन में लगे रहने पड़ा।

## लूट ली थी खाद

ग्वालियर- चंबल क्षेत्र में तो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। गोदाम से खाद लूटने जैसी घटना भी हुई और कांग्रेस विधायक मनोज चावला के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज हुआ था। चुनाव के वर्ष में ऐसी स्थिति फिर निर्मित न हो, इसलिए सरकार पहले से व्यवस्था बनाने में जुट गई है। शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को 11 लाख टन यूरिया, डीएपी, एनपीके मई तक देने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए अग्रिम भंडारण के लिए खाद मिलना प्रारंभ हो गया है।

## मार्कफेड बढ़ाएगा वितरण समितियों की संख्या

उधर, सहकारिता विभाग ने खाद वितरण सहकारी समितियों की संख्या 110 से बढ़ाकर 160 करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बीज उत्पादक समिति, कृषक उत्पादक समिति, फल-फूल उत्पादक समिति के साथ- साथ अन्य सहकारी समितियों से भी खाद उपलब्ध कराई जाएगी। साथ जिन क्षेत्रों में विपणन समितियों के गोदाम नहीं हैं वहां राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सेल प्रामोटर नियुक्त कर खाद बांटी जाएगी ताकि किसानों तक सरलता के साथ समय पर खाद पहुंच जाए।

किसानों को आवश्यकता के समय पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए, इसके प्रबंध कर लिए हैं। मई तक सभी जिलों में खाद पहुंच जाएगी और सहकारी समितियों के माध्यम से किसान अग्रिम भंडारण भी कर सकेंगे। पूरे सीजन में 27-28 लाख टन खाद की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा नियमित तौर पर की जाती रहेगी।

**अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव कृषि**

### राज्य में 'मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना' को लागू करने का निर्णय

# मप्र सरकार किसानों को 80 प्रतिशत छूट पर देगी मोटे अनाज के उन्नत बीज

### योजना पर 2 वर्षों में 23 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

वर्ष 2023 को देश मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहा है, जिसको देखते हुए देश में मिलेट (मोटा अनाज) फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अधिक से अधिक किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं शुरू की जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सरकार ने राज्य में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।

**मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहन:** योजना के तहत मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा न केवल किसानों को अनुदान पर बीज दिए जाएँगे बल्कि मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमीनार, फूड फेस्टिवल, रोड-शो किए जाएंगे।

## मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना को मंजूरी

मप्र सरकार ने राज्य में आगामी दो वर्षों 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के लिए राज्य मिलेट योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। सरकार इस योजना पर 2 वर्षों में 23 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

## ब्रांडिंग मार्केटिंग देखेंगी समितियां

सहकारी समितियों को महासंघ का सदस्य बनाया जा रहा है। समितियां उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम देखेंगी। किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराएंगे और विपणन केंद्र के रूप में काम भी करेंगी। दरअसल, अभी सबसे बड़ी समस्या जैविक उत्पाद के विपणन की ही है। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की माँग बढ़ रही है।

## मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहन

कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिससे हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। इसलिए किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।

## मोटे अनाज से बने उत्पादों को यहां शामिल किया जाएगा

मध्यप्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार एवं रागी के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। साथ ही मिलेट फसलों के बढ़ते बाजार के दृष्टिगत मूल्य संवर्धन की संभावना भी काफी अधिक है। प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों में जहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक व्यंजन मोटे अनाज का भी रखा जायेगा। छात्रावास एवं मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जायेगी।

### कैबिनेट बैठक में मिली स्वीकृति

# इस बार भी एमएसपी पर मूंग उड़द खरीदेगी मप्र सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में सरकार ने किसानों के द्वारा गर्मी में लागी जाने वाली मूंग एवं उड़द फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर करने का निर्णय लिया है। मंत्री परिषद की बैठक में ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने को स्वीकृति प्रदान की है।

**किसानों को होगा दोगुना फायदा:** मध्य प्रदेश के किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने इसको लेकर कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने से किसानों को लगभग दोगुना फायदा होगा। गत वर्ष मॉर्केट में ग्रीष्मकालीन मूंग की बिक्री लगभग 4 हजार रूपये प्रति क्विंटल हो रही थी। सरकार ने समर्थन मूल्य पर 7 हजार 225 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की थी। मंत्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने इस बार भी वर्ष 2023-24 के लिये किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का किसान हितैषी निर्णय लिया है।

**इस योजना के तहत होगी खरीद:** उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मंत्रि-परिषद ने मंगलवार 11 अप्रैल को हुई बैठक में भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में प्राइस सपोर्ट स्कीम एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2021-22 (विपणन वर्ष 2022-23) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत किसानों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया है।

**7,755 रुपए प्रति क्विंटल एवं उड़द के लिए 6,600 रुपए प्रति क्विंटल का भाव:** प्रति वर्ष केंद्र सरकार द्वारा देश भर में रबी एवं खरीफ सीजन में उपजाई जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा की जाती है। जिस पर ही देश के अलग-अलग राज्यों में इन फसलों की खरीदी की जाती है। केंद्र सरकार ने पिछले खरीफ सीजन में मूंग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रुपए प्रति क्विंटल एवं उड़द के लिए 6,600 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय किया था। सरकार द्वारा इस जायद सीजन में इस भाव पर ही मूंग एवं उड़द की खरीदी की जाएगी।

### आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास

# पशुपालकों को गोपालन के लिए मध्यप्रदेश सरकार दे रही 10 लाख रूपये

भोपाल। मध्यप्रदेश में पशुपालक किसानों के लिए पशुपालन विभाग द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना चलाई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन एंव हितग्राहियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना हैं। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने पशुपालकों से

अपील की है कि आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना का लाभ उठायें। श्री पटेल ने बताया कि वर्ष 2022-23 में योजना में लक्ष्य के अनुसार सामान्य वर्ग के 421, अनुसूचित जनजाति के 16 और अनुसूचित जाति के 38 हितग्राही को लाभान्वित किया गया।

## लागत की 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण द्वारा प्राप्त होगी

मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना में पशुपालक 10 लाख रूपये तक के 5 या इससे अधिक पशु स्वीकृत करा सकते हैं। लागत की 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण द्वारा और शेष राशि मार्जिन मनी की व्यवस्था हितग्राही को स्वयं के अंशदान से करनी होती है। इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से (अधिकतम 25 हजार रुपए तक) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है। पाँच प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करना होती है।

## कितना रहेगी मार्जिन मनी

मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि आचार्य विद्यासागर योजना के तहत मार्जिन मनी सामान्य वर्ग के लिये परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये परियोजना लागत का 33 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रूपये है।

# तपती पृथ्वी और अनाज का संकट, समय पर समाधान जरूरी

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिंड)

साल दर साल पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। सबसे ज्यादा असर तापमान में हो रही बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। इसी प्रकार से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती रही तो आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई आबादी के लिए अनाज का संकट खड़ा हो सकता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। जलवायु परिवर्तन हर किसी को चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव खेती पर देखा जा रहा है। यह कहना गलत ना होगा कि किसानों के इसकी चपेट में आने की संभावना सबसे अधिक रहती है।

भारतीय कृषि प्रमुख रूप से मौसम पर आधारित है और जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले मौसमी बदलावों का इस पर बेहद गहरा असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होना एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। इसके अलावा वर्षा का कम होना, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा की स्थिति देखी जा रही है। जलवायु परिवर्तन के चलते ही असमय वर्षा, ओले पड़ना आदि स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। प्रकृति के बदलते हुए मिजाज के कारण पैदा हो रहीं है यह स्थितियां खेती किसानी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं हैं। इस प्रकार की स्थितियों के कारण खेती लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि किसानों को यह पता होना चाहिए इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से कैसे मुकाबला किया जाए। इसलिए इस समय जरूरत इस बात की है इस समस्या पर चर्चा, गोष्ठियों आदि करने की बजाय धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए धरातल पर पूरी दुनिया में एक साथ काम करने की जरुरत है, तभी इस समस्या का कुछ समाधान किया जा सकता है।

वैश्विक आबादी बढ़ने के साथ पूरी दुनिया में खाद्यान्नों की वैश्विक मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। विकसित देशों में रहने वाले लोगों के भोजन में जहां प्रोटीन की मात्रा अधिक रहती है वही भारत जैसे विकासशील देशों में लोगों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है। इस सब की पूर्ति खेती में पैदा होने वाले खाद्यान्न, दलहन और तिलहन से पूरी होती है। जिस तेजी से पूरे विश्व में आबादी बढ़ रही है और आने वाले 2050 तक यह आबादी का आंकड़ा 9 अरब से ऊपर तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको देखते हुए खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि खाद आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए वैश्विक कृषि उत्पादन 2050 तक दुगना करने की आवश्यकता होगी।

भारत में 120 मिलियन हेक्टर ऐसी भूमि हैं जो किसी न किसी प्रकार की कमी से ग्रस्त है। भारत में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 87प्रतिशत से अधिक है। यही छोटे तथा मझोले किसान इस से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। एक अनुमान के अनुसार भयंकर सूखे की वजह से इन्हें घरेलू उत्पादन में 24 से 58प्रतिशत की कमी का सामना करना पड़ सकता है और घरेलू गरीबी में 12 से 33प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। भारत की कुल कृषि भूमि का 67प्रतिशत भाग मानसून तथा अन्य मौसम में होने वाली वर्षा पर निर्भर है। यदि मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी को समझें तो वर्ष 2050 तक गर्मियों में होने वाली मानसूनी वर्षा में 70प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। मानसूनी वर्षा में आने वाली इस गिरावट से भारतीय कृषि को नुकसान होना तय है। इतना ही नहीं अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि आने वाले 80 वर्षों में खरीफ फसलों के मौसम में औसत तापमान में 0.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप वर्षा भी कमोबेश प्रभावित होगी जिसकी वजह से रबी के मौसम में गेहूं की उपज में 22प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है तथा धान का उत्पादन 15प्रतिशत तक कम हो सकता है।

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक पर नजर डालें तो वर्ष 2019 में भारत को इस सूची में 14वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में भारत के चार अन्य पड़ोसी देश और अधिक ऊंचे स्थान पर हैं म्यांमार तीसरे, बांग्लादेश सातवें, पाकिस्तान आठवें और नेपाल 11 वें स्थान पर है। यह सूचकांक स्पष्ट करता है कि भारत के यह चारो पड़ोसी देश चरम यानि एक्सट्रीम मौसमी घटनाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। इन प्रभावों का लेखा-जोखा पूर्ण रूप से साथ ही संबंधित शब्दों के साथ रखता है। हालांकि भारत इस मामले में भाग्यशाली है कि उसके हिस्से में मानसून की अच्छी वर्षा आती है, लेकिन बढ़ते तापमान की समस्या से भी देश को दो-चार होना पड़ रहा है। बढ़ता हुआ तापमान भारत जैसे देश की खेती किसानी के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

गत वर्ष 2022 के मार्च माह में भारत और पाकिस्तान में पैदा हुई असामान्य शुरुआती गर्मी की लहरों ने 122 साल पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जलवायु परिवर्तन के कारण गत वर्ष मार्च माह में तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण देश में रबी का खाद्यान्न उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं हुआ था। इसके चलते भारत को गेहूं का निर्यात भी रोकना पड़ गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हीटवेव 2022, कारण, प्रभाव और भारतीय कृषि के लिए आगे बढ़ने का रास्ता शीर्षक से एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। जिसमें जलवायु लचीला कृषि (निकरा) कार्यक्रम में राष्ट्रीय नवाचारों के माध्यम से किए गए विश्लेषण को शामिल किया गया है। गर्मी की लहरों से लड़ने, फसलों और मवेशियों की रक्षा करने के तरीकों का सुझाव दिया गया है।

बढ़ता तापमान भारत में खेती-किसानी के निश्चित रूप से चुनौती बन कर उभर रहा है। हीटवेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गर्मियों के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक होती है। देखा जाए तो हीटवेव्स आमतौर पर मार्च और जून के बीच होते हैं। चरम तापमान और परिणामी वायुमंडलीय स्थितियां इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। भारत में गर्मी की लहर का चरम महीना मई में होता है। आईएमडी के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक दशक में गर्मी की लहर के दिनों की संख्या जहां वर्ष 1981 से 1990 के बीच 413 थी वह वर्ष 2011 से 2020 के बीच में बढ़कर 600 तक पहुंच गई है। यहां यह कहना गलत न होगा कि हर दशक में गर्मी की चरम स्थिति के दिनों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा हीटवेव के वर्गीकरण के क्रम में मैदानों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान हीटवेव्स में माना जाता है। यदि वास्तविक अधिकतम तापमान के रूप में देखें तो गर्मी की लहर 45 डिग्री सेल्सियस तथा अत्यंत गंभीर गर्मी की लहर को 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाने को माना गया है।

हीटवेव्स की स्थिति के कारण फसल उत्पादन और बागवानी के उत्पादन में कमी आ रही है। आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार गर्मी के तनाव के कारण 15 से 25प्रतिशत तक की औसत उपज हानि की हो रही है। हीटवेव्स के प्रभाव के कारण नमी, तनाव, सनबर्न, फूलों की बूंद और बागवानी फसलों में कम फल सेटिंग जैसी समस्या देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं पशुओं की मृत्यु और पशुओं की उत्पादन, उत्पादकता और प्रजनन क्षमता में भारी कमी देखी जा रही है। दूध उत्पादन में भी 15 से 20प्रतिशत तक की कमी आई है। मुर्गी पालन में अंडे के उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ ब्रायलर की मृत्यु दर में भी वृद्धि हुई है। हीटवेव के चलते भारत को 2030 तक काम के घंटों का 6प्रतिशत तक की कमी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

### समाधान की आवश्यकता

*इस समाधान के रूप में संरक्षण कृषि और शुष्क कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ-साथ प्रत्येक गांव को विभिन्न मौसमों में फसल, कीटों और महामारियों के बारे में मौसम आधारित पूर्व चेतावनी के साथ समय पर वर्षा के पूर्वानुमान की जानकारी दी जानी चाहिए। कृषि अनुसंधान कार्यक्रमों के तहत शुष्क भूमि अनुसंधान पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके तहत ऐसे बीजों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो सूखे जैसी स्थिति में फसल उत्पादन जोखिम को 50प्रतिशत तक कम कर सकते हैं। गेहूं की फसल रोपण के समय में कुछ फेरबदल करने पर विचार किया जाना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार ऐसा करने से जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति को 60 से 75न्न तक कम किया जा सकता है। किसानों को कम अवधि की सूखा एवं तापमान सहनशील फसलों की प्रजातियों को विकसित करके देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही किसानों को मिलने वाले फसल बीमा कवरेज और उन्हें दिए जाने वाला कर्ज भी की मात्रा बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। सभी फसलों को बीमा कवरेज देने के लिए इस योजना का विस्तार किया जाना चाहिए तथा बीमा कवरेज वास्तविक नुकसान के आधार पर प्रत्येक किसान को दिया जाए तो इस से किसानों के नुकसान की काफी हद तक भरपाई की जा सकती है। खेती में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ाए जाने की जरूरत है। गांवों की में ग्राम पंचायतों के माध्यम से सामाजिक को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ जलवायु स्मार्ट कृषि और शून्य जुताई की पद्धतियों को अपनाते हुए रिसोर्स कंजर्वेशन तकनीकों को खेती में समावेशित करके इस समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा*

# पाचन को बढ़िया करती है ये दाल, कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा कंट्रोल

» डॉ. शिव्या गोखले
» डॉ. पियूष कुमार सिंह

शस्य विज्ञान विभाग ब्रह्मानन्द महाविद्यालय राठ, हमीरपुर (उ. प्र.)

असिस्टेंट प्रोफेसर (कृषि शाखिकी) ब्रह्मानन्द महाविद्यालय राठ, हमीरपुर (उ. प्र.)

अच्छी सेहत और पोषण के लिए रोजाना दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। दाल में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पायी जाती है जिसका सेवन शरीर के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। मूंग दाल के फायदे भी सेहत के लिए अनेकों हैं। मूंग की दाल का सेवन करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। मूंग दाल में मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर कर पोषण देने का काम करते हैं।

मूंग दाल में प्रोटीन, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी -6, नियासिन, थायमिन और फोलेट आदि पाया जाता है, जिसका सेवन बहुत जरूरी होता है। इसमें मौजूद फाइबर की पर्याप्त मात्रा पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। वजन कंट्रोल करने के लिए और कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए इसका सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। मूंग दाल को आप बिना छिलके या छिलके समेत भी खा सकते हैं। आइये विस्तार से जानते हैं मूंग की दाल खाने के फायदे के बारे में।

मूंग की दाल खाने में बेहद स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है जो वजन को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी मानी जाती है। डेंगू की बीमारी हो या सामान्य बुखार दोनों में ही मूंग दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मूंग दाल का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। मूंग दाल खाने से शरीर को ये फायदे मिलते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मूंग की दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। मूंग दाल में फाइबर पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है जो पाचन तंत्र में सुधार के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसका सेवन करने से शरीर में पाचन से जुड़ी अन्य समस्याएं जिसे कब्ज, पेट में गैस की समस्या आदि में बहुत फायदा मिलता है। इसका गर्मी के मौसम में सेवन करने से पेट की गर्मी को दूर करने में भी फायदा मिलता है। आप रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

वजन को कंट्रोल में रखने के लिए मूगं की दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। मूगं की दाल में मौजूद लो कैलोरी वजन को नियंत्रित करने का काम करती है। इसमें फाइबर के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो भूख को कंट्रोल करता है। इसका सेवन करने से आपको बार-बार भूख नहीं लगती है जिससे आपको वजन कम करने में फायदा मिलता है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए मूंग की दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। मूंग की दाल में मौजूद गुण शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित रखने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। आप अगर डायबिटीज के मरीज है तो डॉक्टर की सलाह के आधार पर आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

ब्लड प्रेशर की समस्या में मूंग दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। मूंग की दाल में पोटेशियम, फाइबर और मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में इसका सेवन फायदेमंद होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए आप नियमित रूप से मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं।

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी ब ?ने के लिए मूंग की दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने का काम करते हैं।

स्ट्रेस या मानसिक तनाव आदि को दूर करने में मूंग की दाल का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर आप स्ट्रेस की समस्या का शिकार हैं तो रोजाना इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

**मूंग दाल को डाइट में शामिल करने का तरीका:** मूंग की दाल को आप कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो रोजाना इसकी दाल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूंग दाल को भिगोकर उसकी करी भी बना सकते हैं। अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हैं तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

## गर्मी में मुर्गी के दाने का प्रबंधन

» डॉ. याशिर आमीन राथेर
» डॉ. शानू देवी सिंगौर
» डॉ. शाहबाज हारुन खान
» डॉ. ब्रजमोहन सिंह धाकड़

कुक्कुट विज्ञान विभाग, पशुचिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे.प.वि.वि. जबलपुर (म. प्र.)

पशुचिकत्सा जनस्वास्थय और महामारी विज्ञान विभाग, पशुचिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे. प.वि.वि.जबलपुर (म. प्र.)

मुर्गी पालन का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होने के साथ ही यह बड़ी संख्या में किसानों को रोजगार प्रदान करता है। ग्रीष्म ऋतु का समय मुर्गीपालकों के लिए सबसे कठिन समय होता है। पोल्ट्री शेड में 35 डिग्री से ऊपर का तापमान शरीर के तापमान को समायोजित करने में समस्या पैदा करता है। गर्मी में 1 डिग्री तापमान बढ़ने से मुर्गी 1.5 प्रतिशत कम खाना खाती है। जब तापमान 28-30 डिग्री हो जाता है तो और 5 प्रतिशत कम खाना खाती हैं। जब तापमान 32-38 डिग्री हो जाता है, तो डॉक्टर से परामर्श से उचित देखभाल करनी चाहिए।

**गर्मी का प्रभाव:** तेजे सांस लेना, कम वजन आना, ज्यादा एफसीआर, कम दाना खाना कम और पानी पीना, अंडे के शैल का टूटने, अंडे प्रोडक्शन में कमी।

**मुर्गी के दाने का प्रबंधन:** गर्मी में मुर्गी कम दाना खाती है। इसके नुकसान से बचने के लिये दाने में न्यूट्रिएंट डेंसिटी अधिक रखनी चाहिए, जिससे उसकी न्यूट्रिएंट के आवश्कता पूरी हो जाए। भोजन सुबह और शाम को जब तापमान कम रहे तब देना चाहिए। दोपहर में भोजन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाचन के ताप शरीर का तापमान बढ़ाता है। पाचन से उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए प्रोटीन कम देना चाहिए, साथ-साथ अमीनो एसिड सही मात्रा में मिलाने ताजा और ठंडा पानी पक्षी के लिए लगातार उपलब्ध रहना चाहिए। डेक्सट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड इत्यादि) जैसी दवाएं अधिक गर्मी में शरीर के आयनिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। अधिक मात्रा (20- 30 परसेंट) विटामिन और मिनरल दाने में मिलने चाहिए। भोजन में एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे विटामिन ई और विटामिन सी को शामिल करने से गर्मी तनाव कम होता है। इम्यून मॉडलटेर दाना में और पानी में शामिल करने से गर्मी तनाव कम होता है। मल्टीस्ट्राइन प्रोबिओटिक देने से मुर्गियों में ज्यादा दाना खाती है और अंडे का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। एंटीफंगल दाने में उसे करने चाहिए, गर्मियों और अधिक आद्रता में फंगस ग्रोथ बढ़ जाती है।

**सावधानियाँ:** लिटिर मटेरियल के मोटाई 2-3 इंच होनी चाहिए। केक बनने से बचना चाहिए। मुर्गियों के घेर पूर्व-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे हवा का संचालन ठीक रहता है। ट्रांसपोर्टेशन, चोंच काटना, वैक्सीनशन करना, ठन्डे तापमान में करना चाहिए। एक जगह पर पक्षियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। जरूरत से अधिक जगह होनी चाहिए। छत पर दिन में 3-4 बार पानी छिड़कने से शेड का तापमान 5डिग्री से 10डिग्री फा. तक कम हो जाता है। छत पर तिनकों/घास फूस के उपयोग से तापावरोधन बनाना, या चूने की मोटी परत के साथ छत की पुताई करनी चाहिए।

## आधुनिक खेती में कृषि यंत्रों की अहम भूमिका, किसानों के लिए काफी उपयोगी

# खेती को सुगम बनाते हैं ये आधुनिक कृषि यंत्र

भोपाल। जागत गांव हमार

आधुनिक खेती में कृषि यंत्रों की अहम भूमिका है। कृषि यंत्रों ने खेती से जुड़ी गतिविधियों को किसानों के लिए सुगम बनाया है। कृषि यंत्रों और उपकरणों की मदद से समय की बचत के साथ ही लागत में कमी आती है। आज हम आपको खेतीबाड़ी में काम आने वाले 5 कृषि यंत्रों के बारे में बता रहे हैं। ये कृषि यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी हैं। आइए जानते हैं इन यंत्रों की खासियत और लाभ।

### 1. मिनी पावर टिलर

ये खेतीबाड़ी की एक ऐसी मशीन है, जो मिट्टी को ढीला करने और रोपण से पहले और फसलों को लगाने के बाद मिट्टी को चिकना करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये खरपतवार को भी नियंत्रित करती है। पावर टिलर मशीन, फसल की निराई-गुड़ाई जैसे कार्य आसान कर देती है। ये मशीन ईंधन से चलती है। इस मशीन को चलाना सरल है। ऑपरेटर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पावर टिलर मशीन को बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए टाइन कवर होता है। आसान गति नियंत्रण के लिए लीवर और ऊंचाई सेट करने के लिए हैंडल दिए होते हैं। देश में कई कंपनियां इसका प्रॉडक्शन कर रही हैं।

### बीज प्लांटर

इस मशीन की मदद से मक्का, बीन्स, मूंगफली, कॉटन प्याज, सोयाबीन, राजमा, मटर, ब्लैक ग्राम, मूंग, बीन्स के बीजों की बुवाई आसानी से की जा सकती है। ये मैन्युअल रूप से संचालित एक डिवाइस है, जिसे ऑपरेट करना आसान है। खाद डालने के काम से लेकर पौधे भी लगा सकती है। बीज और उर्वरक का सही तरह से फैलाव कर सकती है। किसान बीज को रोपने की दूरी भी खुद से तय कर सकते हैं। ये जमीन की सतह से 8 से 12 इंच नीचे जा सकती हैं। गीली मिट्टी में भी ये बखूबी काम कर सकती है।

### ड्रिप सिंचाई किट

बाजार में फुली ऑटोमेटिक ड्रिप सिंचाई किट उपलब्ध है। ड्रिप सिंचाई किट में फील्ड इंस्टॉलेशन और संचालन के लिए सभी आवश्यक पार्ट शामिल हैं। इस किट में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक वॉटर टाइमर, फीडर लाइन पाइप, मेनलाइन कोन कनेक्टर, टैप एडाप्टर, होल्डिंग स्टिक, ड्रिप होल पंचर,होल प्लग, मेनलाइन स्ट्रेट कनेक्टर, फ्लेक्सनेट पाइप, ड्रिपलाइन, इंस्टॉलेशन मैन्युअल समेत कई और चीजें मिलती हैं। आप घर में न भी हों, या छुट्टी पर हों तो भी ये आपके बगीचे को अच्छे से पानी देगा। बालकनी गार्डन, टेरेस गार्डन से लेकर आउटडोर के लिए ये ड्रिप सिंचाई किट उपयुक्त है। आप इसकी मदद से अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी का शेड्यूल सेट कर सकते हैं।

### क्रॉप कटर मशीन

फसलों की कटाई में कई श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। अकेले करने बैठें तो काफी वख्त लगता है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए बाजार में कई कंपनियों ने फसल काटने वाली मशीनें उतारी हैं। इन मशीनों को क्रॉप कटर मशीन कहा जाता है। बाजार में कई रेंज में ये मशीनें उपलब्ध हैं। ऑनलाइन भी ऐसी मशीनें मिल रही हैं, जिनका दाम 15 हजार से 40 हजार के बीच होता है। ये मशीन गेहूं, चावल, गन्ना, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, हरा चारा और घास काटने जैसे काम आसानी से कर देती है। यह मिट्टी की सतह से सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर फसलों को काटती हैं। इनमें लगे अतिरिक्त वीडर अटैचमेंट, खरपतवार को हटाने का भी काम करते हैं। इसके अलावा, डीजल से चलने वाली ये मशीन घास ट्रिमिंग, लॉन ट्रिमिंग, खेत की निराई-गुड़ाई भी करती है। इन मशीनों की खासियत है कि छोटे या बड़े किसान खुद की फसल की कटाई करने के साथ ही किराये पर भी इन मशीनों को चलाने के लिए दे सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से कटाई का पैसा मिलेगा और इससे अच्छी कमाई हो सकती है।

### स्प्रेयर पंप

फसलों पर कीट-रोगों के लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। कीट-रोगों के प्रकोप से फसल नष्ट हो जाती है। पौधे के विकास को खरपतवार भी नुकसान पहुंचाते हैं। कीट, बीमारियों और खरपतवार की रोकथाम के लिए कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेयर पंप की मदद से इन कीटनाशकों/उर्वरकों को फसल पर छिड़का जाता है। कई प्रकार के स्प्रेयर भिन्न-भिन्न कार्य करने के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। इनकी उपयोगिता अनेक कारकों पर निर्भर करती है। छोटे किसानों के लिए स्प्रेयर पंप मशीन बड़े काम की हैं। ये मशीन कई तरह के फंक्शन के साथ आती है। इसे बैटरी और हाथ, दोनों तरीकों से ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें आप एक बार में 18 लीटर तक कीटनाशक भर सकते हैं। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद 20 से 25 बार उपयोग कर सकते हैं। इस स्प्रेयर पंप का कृषि, रसायन, खेती, बागवानी और भी कई तरह की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रॉडक्ट पर 6 महीने से लेकर एक साल तक की वॉरन्टी होती है।

## बाजार में मिलती है 70 लाख रुपये किलो तक कीमत

# मुरैना में लगेगी मधुमक्खी डंक प्रोसेसिंग यूनिट, किसानों को मिलेगा फायदा

अवधेश डंडोतिया, मुरैना

मधुमक्खी के डंक से आपने इंसानों को जान गंवाते हुए देखा होगा, लेकिन ये डंक आपको मालामाल भी कर सकता है। मधुमक्खी का जो डंक जहर और दर्द से भरा होता है, वही डंक 70 लाख रुपये में बिकने को तैयार है। मध्य प्रदेश के मुरैना में इस डंक के प्रोसेसिंग के लिए यूनिट भी लगाया जा रहा है। महात्मा गांधी सेवा आश्रम में लग रहे इस यूनिट पर 4 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इससे संबंधित प्रकिया शुरू हो चुका है। यहां लगने वाली शहद की प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा शहद की गुणवत्ता की जांच परख करने के बाद उसकी पैकिंग की जाएगी। इसकी ब्रांडिंग भी की जाएगी। इसकी क्षमता 1.5 टन निर्धारित की गई है।

**मधुमक्खी पालकों को किया जाएगा प्रशिक्षित**- महात्मा गांधी सेवा आश्रम में शहद की यूनिट लग जाने के बाद इन मधुमक्खी पालकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए बाकायदा मधुमक्खी पालकों को ट्रेंड भी किया जाएगा। शहद के साथ-साथ महात्मा गांधी सेवा आश्रम में लगने वाली यूनिट में विशेष मशीन के माध्यम से मधुमक्खियों के डंक निकालने का काम भी किया जाएगा। मधुमक्खी के डंक की राष्ट्रीय बाजार में बहुत डिमांड रहती है और राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 70 लाख रुपये तक बताई जा रही है। बता दें कि मशीन के माध्यम से मधुमक्खी का डंक निकालने के बाद मधुमक्खी के जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा। मधुमक्खी के शहद से लेकर उसके छत्ते तक से निकलने वाले गोंद का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। इस तरह महात्मा गांधी सेवा आश्रम में शहद की यूनिट लगने के बाद मधुमक्खी पालकों को काफी मुनाफा होना शुरू हो जाएगा।

# गर्मी में गाय-भैंस में कैसे बढ़ेगी दूध की मात्रा, जानें क्या कहते

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती-किसानी की तरह ही अब पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बनकर उभर रहा है। दूध की बढ़ती मांग के बीच गांव में लोग पशुपालन को अपनी आजीविका का हिस्सा बना रहे हैं। गाय-भैंस पालने से खेती के लिए जैविक खाद का इंतजाम भी हो जाता है। ये बचत और आमदमी का अच्छा साधन है। पशु विशेषज्ञों की मानें तो इस बिजनेस से मुनाफा कमाने के लिए पशुपालकों को पशुओं की सेहत पर खास फोकस करना चाहिए। अच्छी नस्ल के पशुओं को बेड़े में शामिल करना चाहिए. ये हर हालात में खुद को ढ़ाल लेते है। हालांकि गर्मियां हर नस्ल के पशु के लिए परेशानियों से भरी होती है। धूप की तपिश और लू लगने से पशुओं में तनाव बढ़ जाता है और सुस्ती आ जाती है। इसका सीधा असर दूध की मात्रा पर पड़ता है। दूध की मात्रा में गिरावट आ जाती है और पशुपालकों को नुकसान होने लगता है। इस परेशानियों को दूर करने के लिए पशुपालकों को पशुओं के खान-पान का ख्याल रखना होगा। दूध मात्रा बढ़ने में कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं।

### इन बातों का रखें खास ध्यान

- गर्मी से पशुओं को बचाने के लिए सुबह या शाम के समय पशुओं को तालाब में नहलाने ले जाएं।
- पशुओं को दिन 4 से 5 बार साफ और ठंडा पानी पिलवाएं।
- ज्यादा तापमान बढ़ने पर एक बाल्टी पानी में 250 ग्राम चीनी और 20-30 ग्राम नमक का घोल बनाकर पशु को पिलाएं।
- सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पशु को छायादार स्थान पर बिठाएं। इस दौरान चारागाह में ना छोड़ें।
- हरा चारा नहीं है तो सूखे चारे के साथ कुछ मात्रा में सप्लीमेंट्स खिला सकते हैं।
- 10 किलो सूखे चारे में 4 किलो मक्का का दिया, 3 किलो खल, 2.5 किलो चोकर, 500 ग्राम गुड़ मिलाकर फीड बनाएं और रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाएं।

**इन उपायों से पशुओं में बढ़ेगा दूध** गर्मी के मौसम में पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में पशुओं को लोबिया घास खिलाएं। लोबिया घास में फाइबर, प्रोटीन और औषधीय गुण होते हैं, जो पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाते हैं। दूध बढ़ाने और पशुओं की अच्छी हेल्थ के लिए अजोला घास भी खिला सकते हैं। ये घास पानी में उगाई जाती है। पोषण से भरपूर ये ग्रीन फीड पशुओं के लिए संजीवनी समान है।

### क्यों कम हो जाता है पशुओं में दूध

गर्मी और धूप की तेज तपिश से पशुओं में तनाव बढ़ जाता है। पशु धीरे-धीरे सुस्त हो जाती है और लू लगने से शरीर का भी तापमान बढ़ जाता है। यदि समय पर उपाय ना किए जाएं तो पशु में थकावट, चक्कर, बेहोशी, त्वचा बेजान होने जैसी दिक्कतें हो जाती है।

### 6 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के मुकाबले सिकुड़े हुए और टूटे हुए अनाज की सीमा में 18 प्रतिशत तक की ढील

# गेहूं खरीद के मापदंडों में सरकार ने दी ढील, किसानों को लाभ

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है, ताकि संकटग्रस्त बिक्री को रोका जा सके और साथ ही किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने इन राज्यों के कुछ हिस्सों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन राज्य सरकारों ने खरीद मानदंडों में ढील देने की मांग की थी। वर्तमान में, मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद चल रही है, जबकि अन्य राज्यों में असामयिक बारिश के कारण इसमें देरी हुई है। राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर गेहूं की खरीद करती है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि फील्ड सर्वे के बाद हमने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है ताकि किसानों की कठिनाई को कम किया जा सके और गेहूं की बिक्री में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। सरकार ने समान विनिर्देशों के तहत 6 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के मुकाबले सिकुड़े हुए और टूटे हुए अनाज की सीमा में 18 प्रतिशत तक की ढील दी है।

**कटौती लागू नहीं होगी**

सुबोध ने कहा कि छह प्रतिशत तक सिकुड़े और टूटे हुए अनाज वाले गेहूं के मूल्य में कोई कटौती लागू नहीं होगी। मूल्य कटौती 10 प्रतिशत तक चमक हानि वाले गेहूं पर लागू नहीं होगी, जबकि 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चमक हीन गेहूं पर फ्लैट आधार पर 5 रुपए 31 पैसे प्रति क्विंटल की दर से मूल्य कटौती की जाएगी। इसके अलावे क्षतिग्रस्त और हल्के क्षतिग्रस्त अनाज की मात्रा 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

### 10 अप्रैल तक 13.20 लाख टन गेहूं खरीदी

सुबोध ने कहा कि भंडारण के दौरान नियमों में ढील के तहत खरीदे गए गेहूं के स्टॉक की गुणवत्ता में किसी भी तरह की गिरावट पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। इस गेहूं का वितरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के 10 अप्रैल तक 13.20 लाख टन गेहूं खरीदा है, जिसमें ज्यादातर मप्र से हैं। इसी अवधि में पंजाब में लगभग 1,000 टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि हरियाणा में 88,000 टन गेहूं खरीदा गया है।

### उत्पादन रिकॉर्ड का अनुमान

केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 34.2 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष हुई 19 मिलियन टन गेहूं खरीद के मुकाबले अधिक है। पिछले साल लू और बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में मामूली गिरावट के कारण गेहूं की खरीद में गिरावट आई थी। हालांकि, इस साल उत्पादन रिकॉर्ड 112.2 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

### मध्य प्रदेश में जैविक खेती का रकबा 16.37 लाख हेक्टेयर

## -मध्यप्रदेश में खाद के उत्पादन से भी जुड़ेंगी

# जैविक खेती को बढ़ावा देंगी सहकारी समितियां

### सभी समितियां जैविक खेती के काम से जुड़ेंगी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने जा रही है। खाद-बीज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण और उपार्जन का काम करने वाली सहकारी समितियां अब किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने का काम भी करेंगी। ये किसानों को इसके लाभ बताएंगी और विपणन व्यवस्था से भी जुड़ेंगी। जैविक खाद के उत्पादन से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इसके लिए चार हजार 536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को नवगठित होने वाले राज्य जैविक सहकारी महासंघ का सदस्य बनाया जाएगा। महासंघ के गठन के लिए पंजीयक राज्य सहकारी संस्थाएं को आवेदन किया जा चुका है। प्रदेश में जैविक खेती का कुल क्षेत्र 16 लाख 37 हजार हेक्टेयर है। वर्ष 2021-22 में जैविक उत्पाद का उत्पादन 14 लाख टन रहा है। पांच लाख टन से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात किए गए थे। इसे और विस्तार देने के लिए सरकार ने जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने कृषि, उद्यानिकी के साथ सहकारिता विभाग को जोड़ा है।

### जैविक महासंघ का होगा गठन

सहकारिता विभाग ने केंद्र सरकार की पहल पर नए क्षेत्रों में सहकारी समितियां गठित करने की कार्ययोजना बनाई है। इसके अंतर्गत जैविक सहकारी महासंघ का गठन किया जा रहा है। इसमें नई समितियां बनाने के साथ सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को सदस्य बनाया जाएगा ताकि वे किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर सकें। प्रदेश की सहकारी समितियों से 50 लाख किसान जुड़े हैं।

### समितियां करेंगी ब्रांडिंग

सहकारी समितियों को महासंघ का सदस्य बनाया जा रहा है। समितियां उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम देखेंगी। किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराएंगे और विपणन केंद्र के रूप में काम भी करेंगी। दरअसल, अभी सबसे बड़ी समस्या जैविक उत्पाद के विपणन की ही है। यही कारण है कि किसान जैविक खेती करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं।

कुछ समितियों को खाद बनाने के काम में भी लगाया जाएगा। इसके लिए प्रस्तावित गोबरधन योजना से इन्हें जोड़ा जाएगा। पशुपालन विभाग गोशालाओं में गोबर, गौमूत्र खरीदने और उससे खाद बनाने की योजना तैयार कर रहा है। पंजीयन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करके आवेदन कर दिया है। प्रक्रिया पूरी होती है महासंघ की गतिविधियों को विस्तार दिया जाएगा।

**मनीष जोशी, संचालक, महासंघ**

### किसानों को दिया गया प्रशिक्षण

# विलुप्त हो रही कोदो-कुटकी रागी को सहेजें किसान भाई

डिंडौरी। जागत गांव हमार

अखिल भारतीय समन्वित लघुधान्य अनुसंधान परियोजना, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, डिण्डौरी द्वारा आदिवासी उपयोजना में कृषि विज्ञान केन्द्र, डिण्डौरी में एक दिवसीय कृषक प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण कोदन फसलें जो कि इस क्षेत्र से विलुप्त हो चुकी हैं को प्रदर्शनी के माध्यम से कृषकों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉ. डी.एन. श्रीवास वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं केन्द्र प्रभारी ने कोदन फसलों जैसे- कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, चीना आदि की जानकारी किसानों को दी।

कृषि विज्ञान केन्द्र प्रभारी डॉ. पी.एल.अम्बूलकर कीट वैज्ञानिक द्वारा लघुधान्य फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधियों के रोकथाम से संबंधित जानकारी किसानों को दी। साथ ही श्रीअन्न के मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण संबंधी जानकारी केन्द्र की वैज्ञानिक डॉ. मनीषा श्याम द्वारा किसानों को दी गई। डॉ. गीता सिंह वैज्ञानिक विस्तार सेवाएं द्वारा सभी किसानों को मोबाईल संदेश एवं अन्य विस्तार योजनाओं के बारे में अवगत कराया। डॉ. सतेन्द्र कुमार मत्स्य वैज्ञानिक द्वारा कृषकों को लघुधान्य फसलों के साथ अतिरिक्त आय हेतु मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई साथ ही श्री अवधेश कुमार पटेल कार्यक्रम सहायक (उद्यानिकी) द्वारा क्षेत्र में उगाई जाने वाली उद्यानिकी फसलों के बारे में जानकारी दी। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को लघुधान्य फसलों के उन्नत बीज, जैविक खाद, एवं अंर्तशस्यन औजार को प्रदर्शित करते हुए कृषकों को वितरण किया गया। कार्यक्रम में केन्द्र के कर्मचारी बी.पी.कुरील, आस्था प्रधान मरावी, सुनील कुमार एवं मदनमोहन पवार की उपस्थिति एवं सहयोग सराहनीय रहा।

### वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदा से हुआ था फसलों को नुकसान

# प्रदेश में 25 लाख किसानों को मिलेगा 2,900 करोड़ का फसल बीमा

भोपाल। मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को अगले माह दो हजार 900 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिलेगा। वर्ष 2021-22 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित खरीफ और रबी फसलें प्रभावित हुई थीं। सरकार ने सर्वे कराकर बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए थे, जिन्हें अब अंतिम रूप दे दिया है। अब कार्यक्रम करके इस राशि को किसानों के खातों में अंतरित किया जाएगा। प्रदेश में 44 लाख से ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया था। अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थीं। सरकार ने सर्वे कराकर बीमा कंपनियों को दावे प्रस्तुत किए थे। इनका परीक्षण पूरा होने के बाद बीमा दावों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

### किसानों को होगा वितरण

दो हजार 900 करोड़ रुपए का बीमा किसानों को वितरित किया जाएगा। इसकी सूची इस माह के अंत तक कृषि विभाग को मिल जाएगी। इसके बाद राशि किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। खरीफ और रबी सीजन की राशि एक साथ दी जाएगी या अलग-अलग यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्तर पर निर्धारित होना है।

### सीएम को भेजा प्रस्ताव

इसका प्रस्ताव कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 2022-23 के फसल बीमा की प्रक्रिया भी तेजी के साथ पूरी की जा रही है ताकि सितंबर के पहले यह राशि भी किसानों के खातों में जमा करा दी जाए।

-इज्जत का प्रतीक अफीम पट्टा, नहीं छोड़ना चाहते किसान

# मंदसौर में अफीम की खेती हुई महंगी अन्नदाताओं को दाम मिल रहे पुराने

## -मंदसौर व नीमच जिले में काश्तकारों के नाम पर राजनीति

मंदसौर। गौरव तिवारी, जागत गांव हमार

मंदसौर में अफीम के पट्टे, औसत और उसके दाम को लेकर काफी हद तक चुनाव भी प्रभावित होते रहे हैं। इसका असर यह होता हैं कि लोकसभा के चुनावी घोषणा पत्र में अफीम की सरकारी खरीद में दाम 10 हजार रुपए किलो तक कराने का वादा किया जाता है। लेकिन 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया हैं दाम में एक रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि हर साल अफीम किसानों को राजनीतिक दल कुछ न कुछ लालीपाप देते ही रहते हैं। पांच साल पहले सांसद सुधीर गुप्ता ने गांवों में किसानों से कहा था कि अफीम खरीदी के दाम न्यूनतम 5 हजार रुपए किलो तक हो गए हैं। उस समय किसानों ने गांव-गांव में स्वागत कर मालाएं भी पहनाई थी पर अभी भी किसानों न्यूनतम 850 रुपए से अधिकतम 3500 रुपए किलो तक के ही दाम तय है। हालांकि किसानों को औसत 1100 से 1800 रुपए किलो का ही भुगतान होता है। संसदीय क्षेत्र में आने वाले मंदसौर-नीमच जिलों में अफीम काश्तकारों के नाम पर खूब राजनीति होती है।

लंबे समय तक क्षेत्र से सांसद रहे स्व. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी समय-समय पर अफीम नीति में परिवर्तन कराने के साथ ही दाम बढ़ाने के भी वादे करते रहे पर दाम वही के वही रहे। वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता इन सबसे आगे निकल गए। जनवरी-फरवरी 2017 में बही पार्श्वनाथ फंटे पर अफीम किसानों के धरने पर जाकर घोषणा की थी कि अब सरकार अफीम के दाम 5 हजार रुपए प्रति किलो देगी। इससे किसान भी खुश हुए और सांसद का कई गांवों में स्वागत कर साफे भी बांधे। हालांकि उसके बाद छह साल हो गए हैं। हर साल अफीम की तुलाई हो रही है पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम 850 रुपए से अधिकतम 3500 रुपए किलो के दाम ही तय कर रखे हैं। किसानों को औसत दाम 1100-1200 रुपए किलो ही मिल रहे हैं।

### किसानों को पट्टे मार्फीन के आधार पर मिल रहे

किसान संतोष पाटीदार बालागुड़ा, पुष्कर पाटीदार, रामेश्वर शर्मा, बद्रीलाल धनगर, राहुल पाटीदार दलौदा रेल, शांतिलाल पाटीदार धमनार, राधेश्याम पाटीदार दलौदा रेल, अनिल शर्मा जवासिया, राजेश शर्मा जवासिया, राजेश पाटीदार ने बताया कि विभाग द्वारा मार्फीन के प्रश को आधार मानकर पट्टे दिए जा रहे हैं जबकि किसानों को मूल्य देते समय अफीम की गाढ़ता को मानक आधार मान रहे हैं। जब मार्फीन का आधार मानकर लाइसेंस दिए जा रहे हैं तो किसानों को उपज का मूल्य भी इसी आधार पर दिया जाना चाहिए। उच्च क्वालिटी की अफीम के भाव 3500 रुपए आज तक किसी किसान को नहीं दिए गए हैं। यह केवल दिखावा मात्र है। किसानों को उच्च क्वालिटी की अफीम के 1460 रुपए से लगाकर 1800 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है।

### 10 हजार रुपए किलो मिलना चाहिए

ग्राम दौरवाड़ा के खूबचंद शर्मा ने बताया कि अफीम फसल को बच्चों की तरह पालते हैं लागत अधिक लगती है। हंकाई, जुताई, बंधाई, बीज, खाद दवाइयां और मजदूरी कुल मिलाकर 10 आरी में अब 80 से 90 हजार रुपए तक खर्च आता है। लागत के आधे भाव भी नहीं मिलने से किसान परेशान और दुखी है। अफीम के भाव न्यूनतम 10 हजार रुपए प्रतिकिलो से प्रारंभ किए जाए ताकि किसानों को उसकी लागत मूल्य का भाव मिल सके।

### मंदसौर में 20 हजार से अधिक पट्टाधारी

अंग्रेजों के शासनकाल में मंदसौर संसदीय क्षेत्र और इससे सटे राजस्थान के चित्तौड़, कोटा, प्रतापगढ़ व झालावाड़ में अफीम की खेती शुरू की गई थी। मंदसौर जिले की समशीतोष्णत जलवायु इसके अनुकूल होने से सर्वाधिक 20 हजार से अधिक पट्टे इसी जिले में हैं। गांवों में अफीम पट्टाधारी किसान को अलग ही सम्मान मिलता हैं इसलिए वह कड़ाके की सर्दी में रात में भी खेतों में रखवाली करते हैं। डोडे में चीरा लगाने से पहले मां कालिका की पूजा करते हैं। जेब से रुपए लगाकर भी अफीम की खेती करता है। इधर बाजार में अफीम के सह उत्पाद पोस्तादाना के भाव 2000 रुपए किलो तक हो गए हैं पर सरकार ने अफीम के दाम अभी तक नहीं बढ़ाए हैं।

यह केंद्र सरकार की फसल है। जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को प्रतिवर्ष बोनस और महंगाई भत्ता मिलता है उसी प्रकार अफीम काश्तकार को फसल का नि:शुल्क बीमा एवं बोनस का लाभ मिलना चाहिए। जो काश्तकार फसल की अच्छी उपज देता है उसका राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होना चाहिए। आज भाव सही और नीति स्पष्ट नहीं होने से किसान परेशान और दुखी हैं।

**योगेंद्र जोशी, आकोदड़ा**

अफीम के खेत में 15-20 दिन की लुणी चीरनी का खर्च 30 हजार रुपए होता है। खाद-बीज, हंकाई, जुताई, निदाई-गुड़ाई वह सभी अलग हैं। विभाग किसानों से 870 रुपए किलो की न्यूनतम दर पर खरीदता है। इससे तो लागत भी नहीं निकलती है।

**कांतिलाल पाटीदार, आकोदड़ा**

अफीम किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी कुछ कार्य किया है। कई लोगों के पट्टे वापस भी कराए हैं। अफीम के दाम बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के टेरिफ कमीशन तक मांग की जा चुकी है। जल्द ही इसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे।

**- सुधीर गुप्ता, सांसद**

नरवाई जलाने से भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के साथ वातावरण का तापमान भी बढ़ जाता है: डा. अखिलेश कुमार

# नरवाई जलाने का नुकसान और फसलों को कीटों से बचाने का उपाय

रीवा। जागत गांव हमार

पौध सरंक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार कृषि विज्ञान केंद्र रीवा द्वारा कृषको को समसामयिक सुझाव एवं सलाह में किसान खेत में नरवाई न जलाए क्योंकि भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के साथ वातावरण का तापमान भी बढ़ जाता है। मृदा में पाये जाने वाले लाभदायक जीव या सूक्ष्मजीव के नष्ट होने के साथ.साथ पर्यावरण भी दूषित होता है और भूमि कठोर हो जाती है। खेत में पड़ा कचरा भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हे। खेती का देष की आर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। अगर नरवाई न जलाकर स्ट्रा रीपर का प्रयोग करके भूसा बनाकर पशुओ को खिला सकते है और जमीन मे मिट्टी पलटने वाले हल से पलटकर खेत में मिलाना चाहिए।

### उर्द एवं मूंग को पीला रोग से कैसे बचाएं

उर्द एवं मूंग की फसल में पीला रोग लगने पर इमीदाक्लोप्रिड्ड 17.8 एसल की 8 मिली मात्रा प्रति टंकी या थायोमेथोसाम एवं इमीदाक्लोप्रिड्ड की मिश्रित दवा की 10 मिली मात्रा प्रति टंकी या 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इस समय रीवा में प्याज में झुलसा रोग का प्रकोप देखा जा रहा है जिसमें पौधों की पत्तियां ऊपर से पीली पड़कर सूखने लगती है इसके नियंत्रण हेतु कैप्टान हेक्साकोनोजोल की मिश्रित दवा की 30 ग्राम मात्रा प्रति टंकी या प्रोपिकोनाजोल 13.9 डायफेनोकोनाजोल 13.9 ईसी की मिश्रित दवा की 20 एम एल मात्रा प्रति टंकी या टेबुकोनाजोल 25.9 ईसी की 25 एम एल प्रति टंकी की दर से प्रकोपित फसल पर छिड़काव करना चाहिए। उर्द, बरबटी एवं मूंग की फसल में पत्ती काटने वाले कीट का प्रकोप देखा जा रहा है इसके नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफोस 50 ईसी की 25 मिली प्रति टंकी या थायमेथाक्साम 12.6 लेम्ब्डा सायहैलोथ्रिन 9.5 जेडसी मिश्रित दवा की 10 मिली मात्रा प्रति टंकी (15 लीटर पानी) की दर से छिड़काव करना चाहिए। कदूवर्गीय फसलो में फल मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई देने पर मेलाथियान 50 ईसी की 15 मिली के साथ 200 ग्राम गु? प्रति टंकी की दर से प्रकोपित फसल पर छि?काव करना चाहिए।

# बलराम एप: किसानों की समस्या का होगा समाधान, विशेषज्ञों से सीधे होगी बात

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे है। इसी कड़ी में कई मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए गए हैं, जिनसे किसानों को सही समय पर सही कृषि कार्य के लिए एडवायजरी मिल जाती है। कई एप्स मोबाइल पर ही मौसम से जुड़ी अपडेट्स और विशेषज्ञों द्वारा जारी कृषि सलाह भी दी जाती है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक इसी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन 'बलराम' लॉन्च किया गया है। टू वे कम्यूनिकेशन फीचर्स वाला ये एप्लीकेशन मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लॉन्च किया जा चुका है।

## बलराम एप के खास फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इंडो जर्मन तकनीक के कंबाइन प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए बलराम एप्लीकेशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को दी गई है। एक्सपर्ट्स की मानें तो बलराम एप्लीकेशन को मिट्टी की सेहत को बरकरार रखने और कृषि कार्यों में आ रहीं समस्याओं के समाधान के लिए विकसित और लॉन्च किया गया है। राज्य में पहली बार किसानों अपने फोन पर खेती से जुड़ी एडवायजरी ले पाएंगे। साथ ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से भी संपर्क कर सकेंगे। इस एप्लीकेशन में किसानों की सुविधा के लिए अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाएं हैं।

## 10 जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा

पहले चरण में मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बलराम एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। फिल्हाल खरीफ सीजन के लिए जबलपुर, सागर, शहडोल, सिंगरौली, रीवा, बालाघाट, मंडला, कटनी, छतरपुर और दमोह को शामिल किया गया है। इस एप्लीकेशन से किसानों को राज्य, जिला, विकासखंड और ब्लॉक स्तर की कृषि संबंधी जानकारियां दी जाएंगी। पहले चरण में बलराम एप्लीकेशन से 25,000 किसानों को जोड़ा जा रहा है। इस एप के बेहतर संचालन के लिए जबलपुर कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को भी तकनीकी ट्रेनिंग देकर मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किया जाएगा।

### ग्वालियर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2023 का शुभारंभ

# आज पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा भी मान रही: नरेंद्र सिंह तोमर

ग्वालियर। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि आज हम अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से बाहर आए हैं, आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ है और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कारण। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय था जब हमारे देश में प्रतिभा थी और हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इन प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का वातावरण ही नहीं था। यही वजह है कि देश में प्रतिभाएं कुंठित हो रही थी और उन्हें विदेशों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस स्थिति को समझा और देश में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया, जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बदलाव आया है। श्री तोमर ने कहा कि 2014 से पहले देश में कुल 31-32 ही स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 6,500 से भी ज्यादा हो गई है। अकेले कृषि क्षेत्र में ही इनकी संख्या 2,000 से ऊपर है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है और इसका लोहा भी मान रही है।

## पूरी दुनिया में बनी भारत की पहचान

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनी है और दुनियाभर में भारत की ताकत भी बड़ी है। यही वजह है कि जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को यह कहते हुए रुकवा देते है कि पहले हमारे बच्चों को बाहर निकलने दें तो भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री जी का परिचय कराते हुए कहते हैं कि एक सूर्य, एक विश्व और एक मोदी तो पूरी दुनिया को भारत की ताकत पर गर्व होता है। स्टार्टअप कानक्लेव में मध्य प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, सांसद विवेक शेजवलकर, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाशचंद्र, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापति, अखिल भारतीय महामंत्री घनश्याम ओझा और अखिल भारतीय सचिव समीर मूंदड़ा भी उपस्थित रहे।

# किसानों से जैविक उत्पाद खरीदने पर उन्हें प्रमाण पत्र देना जरूरी

### मध्यप्रदेश कमर्शियल टैक्स ऑफिस ने राज्य की 29 संस्थाओं को नोटिस जारी किया

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स विभाग ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने वाले संस्थानों से कहा है कि किसानों से ऑर्गेनिक उत्पाद अगर खरीदे गए हैं, तो उसके ट्रांजैक्शन का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए। जिस किसान के साथ ट्रांजैक्शन किया गया है, उस किसान का विवरण और उसकी पहचान की जानकारी दी जाए।

मध्य प्रदेश कमर्शियल टैक्स ऑफिस ने राज्य की 29 संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। टैक्स ऑफिस ने संस्थानों से कहा है कि वे राज्य में किसानों से जैविक कपास, सुत और सोयाबीन की खरीद का प्रमाण पत्र जारी करें। दरअसल 2017-18 के वित्तीय वर्ष के ब्यौरे मांगे गए हैं, जब वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। इसी में इन जैविक उत्पादों के कमर्शियल लेनदेन के लिए जीएसटी के भुगतान की जानकारी मांगी गई थी। एक महीने पहले जारी एक नोटिस में विभाग ने कहा है कि जो संस्थाएं किसानों से जैविक उत्पाद खरीद रही हैं, उन्हें खरीद का प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। विभाग ने इन संस्थाओं को किसानों का विवरण और किसान की पहचान देने के लिए कहा है।

### इस आधार पर नोटिस जारी

इन संस्थाओं को नोटिस जारी करने वाले मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्स के दो मुद्दे हैं। एक, इस कार्रवाई से तय होगा कि किसानों को जैविक उत्पादों के लिए सही-सही दाम मिले। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सही दाम उन किसानों को मिलना चाहिए जो इसकी खेती करते हैं और बिक्री की प्रक्रिया का पालन करते हैं। साथ ही जो जैविक किसान समूह का हिस्सा हैं. दूसरा, इससे टैक्ट वसूली में भी मदद मिलेगी क्योंकि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खरीद-बिक्री के नाम पर व्यापार हो रहा है, तो उसे टैक्स के नजरिये से भी देखना होगा। इससे सरकारी खजाना बढ़ाने में मदद मिलेगी।

# पशु महामारी तैयारी पहल और एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ लॉन्च

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र ने शुक्रवार को पशु महामारी तैयारी पहल और एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ लॉन्च किया, ताकि संभावित पशु महामारी के लिए भारत की तैयारियों और प्रतिक्रिया को बढ़ाया जा सके और जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक रोगों को नियंत्रित/रोका जा सके। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, यह पहल पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढांचे, रोग निगरानी क्षमताओं, प्रारंभिक पहचान और प्रतिक्रिया में सुधार, पशु स्वास्थ्य पेशेवरों में क्षमता का निर्माण और सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करेगी।

वहीं, सरकार ने 1,228 करोड़ रुपये की विश्व बैंक-वित्तपोषित परियोजना एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शुरू में मप्र सहित भारत के पांच राज्यों को कवर करते हुए एक बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

**100 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट्स प्रदान करना:** एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ परियोजना का लक्ष्य 75 जिला प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, दूरस्थ स्थानों और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 100 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट्स प्रदान करना और 5,500 पशु चिकित्सकों के साथ-साथ 9,000 निजी नैदानिक पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के अलावा 300 औषधालयों और अस्पतालों को उन्नत करना है।

**पशु संसाधनों की रक्षा करने के लिए एक सक्रिय कदम:** केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा, भारत में विविध पशु प्रजाति निवास करते हैं और पशुधन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, हम उभरती हुई और जूनोटिक बीमारियों से उत्पन्न खतरों के प्रति भी संवेदनशील हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)